Madras and all precautions are being taken by the State Government to see that necessary action is taken.

SHRI C. N. VISVANATHAN (Tiruppattur): I talked to th e Chief Minister this morning. Is the hon. Minister giving us the afternoon news?

PROF. MADHU DANDAVATE: Yes.

SHRI C. N. VISVANATHAN: Then it is all right

PROF. MADHU DANDAVATE: This is the latest news that I got 10 minutes ago

---

15.26 hrs.

MOTION RE: TWENTIETH, TWENTY-FIRST AND TWENTY-SECOND REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

AND

DISCUSSION ON THE EMPLOYMENT OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES IN SERVICES AGAINST RESERVED QUOTA—*Contd.*

श्री राम सेवक हजारी (रोसड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कमिश्नर की रिपोर्ट पर मैं अपनी राय जाहिर करना चाहता हूं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि जो आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लिये था, उसकी पूर्ति नहीं की गई और यह सिर्फ एक ही विभाग से नहीं, केन्द्रीय सरकार से ले कर राज्य सरकार तक के जितने भी विभाग थे, उन में जो आरक्षण की पूर्ति होनी चाहिये थी, वह नहीं हो सकी।

मैं जनता सरकार के माननीय मंत्रियों से आग्रह करना चाहूंगा कि हरिजनों की उपेक्षा जो पिछले 30 वर्षों में की गई, क्या आप भी वैसा ही करना चाहते हैं, उन्हीं रास्तों पर चलना चाहते हैं? यदि नहीं, और बुनियादी तौर पर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो इस सरकार को कुछ करना होगा।

पिछली सरकार ने पूरे भारत को ही नहीं, दुनिया को यह दिखाने के लिये कि हमने हरिजनों को जमीन दी है, बन्धुआ मजदूरों को मुक्ति दिलाई है, इसका खूब प्रचार किया। लेकिन मैं इस के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि हरिजनों को यह सुविधा नहीं दी गई, बल्कि उन को और ज्यादा परेशानियों में डाला गया। इस का कारण यही था कि जमीन का वितरण जिस बुनियादी ढंग से होना चाहिये था वह नहीं हो सका। जिस सीलिंग के कारणों से जमीन ली जानी चाहिये थी, मालिकों के कब्जे से हटाना चाहिये था, उन को न हटा कर, कागज के आधार पर हरिजनों के बीच में बांटा, गैर-मजरुआ और आम-खास जमीनों को सरकार ने अपने कब्जे में न लिया, हरिजनों के बीच दिखावटी पर्चे दिये गये, उनको धोती और चादर दी गई, ताकि हरिजनों को संतोष हो कि उन को जमीन मिली है। वास्तविकता यह है कि कुछ जमीनें तो पहाड़ी और अलाभकर की जोत वाली जमीन थी और ऐसी जमीनें थीं, जिस में गंगा का पानी है, बहुत सी जमीनों में कुछ उपज ही नहीं सकता था, जिस जमीन का कोई नामोनिशान ही नहीं था। उन्होंने यह सिर्फ उन के संतोष के लिये नहीं किया था, दुनिया और भारत के लोगों को दिखाने के लिये किया था, कि कांग्रेस की हुकूमत हरिजनों के लिये कार्य कर रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि वास्तविक रूप में जो हरिजनों को देना चाहिए था, वह नहीं दिया गया। इसी के कारण आज ये घटनाएं घट रही हैं और खून खराबा

[श्री राम सेवक हजारी]

हो रहा है। इसका यही कारण है कि गैर-जिम्मेदाराना और गैर-कानूनी ढंग से उन से उनकी जमीनें लेकर हरिजनों मे वितरण किया गया।

आज जब आपात स्थिति से लोग निकले हैं तो अपनी दबी हुई भावना को व्यक्त कर हरिजनो पर जुल्म कर रहे है। यह इस सरकार की नहीं, पिछली सरकार की देन है कि आज हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वह बुनियादी तौर पर चाहती है कि हरिजनों को जमीन दे, उनकी सहायता करे? यदि हां, तो उस को फिर से विचार करना होगा और जो जमीने आबादी के लायक है, जिन पर जमीदारो के कब्जे है, उन के कब्जे से उन्हें निकाल कर हरिजनो को देना पड़ेगा। यह नही कि जमीन उन के कब्जे मे हो और कागजी ढग से हरिजनों के नाम जमीन दिखा दी जाये। आज हरिजनो मे दम नही है कि वह जमीदारो से लड़ सके।

MR. DEPUTY-SPEAKER. I think he can continue on the next day.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now it is 3.30 p. m. We take up the private Members' Business. Shri Yadvendra Dutt.

15.29 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS, BILLS AND RESOLUTIONS

SIXTH REPORT

SHRI YADVENDRA DUTT (Jaunpur): I beg to move:

"That this House do agree with the Sixth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 16th November, 1977."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Sixth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 16th November, 1977."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Bills to be introduced. Shri Chandrappan.

15.30 hrs.

COCONUT BILL*

SHRI C. K. CHANDRAPPAN (Cannanore): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of a Board for the development, promotion and protection of the coconut cultivation and to set up coconut based industries and for these purposes to levy a cess to create a coconut fund and for matters connected therewith.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a Board for the development, promotion and protection of the coconut cultivation and to set up coconut based industries and for these purposes to levy a cess to create a coconut fund and for matters connected therewith.'

The motion was adopted.

SHRI C. K. CHANDRAPPAN: I introduce† the Bill.

---

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 18-11-77.

†Introduction with the recommendation of the President.